[श्री रेवती रमन सिंह]

रुपए प्रति barrel है? आज आपकी सरकार में पेट्रोल और डीज़ल का क्या दाम है? मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि अभी जो टैक्स लगा है, क्या आप उसे माफ करेंगे, जिससे कि आम आदमी को सस्ता पेट्रोल और डीज़ल मिल सके?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Chairman Sir, this is a separate question.

*154. [*The Questioner was absent*]

Installation of more CEPTs in textile industry towns

*154. DR SASIKALA PUSHPA RAMASWAMY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government has taken steps to install more Common Effluent Treatment plants (CETPs) in the textile industry towns of Coimbatore and Tirupur to prevent further pollution of Siruvani and Noyyal rivers;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government intended to open more textile parks in the State of Tamil Nadu;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government is facing opposition on the ground that opening up of more textile parks in the State would further aggravate the pollution of river stretched; and

(f) if so, the details thereof and Government's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI AJAY TAMTA): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Government is implementing the Integrated Processing Development Scheme (IPDS) for enabling the textile processing sector to meet environmental standards through adoption of appropriate technology, specifically in the area of water and waste water management. The Government has sanctioned 3 Projects under the IPDS for setting up Common Effluent Treatment plants (CETPs) with Zero Liquid Discharge (ZLD) systems in the state of Tamil Nadu. The details of the projects are as under:–

Sl. No.	Project Description	State	Year of Sanction	GoI Grant component in the project (₹ in crores)
1.	Kadayampatti Cluster, Erode District-Setting up of ZLD CETP with CPP with Cogen	Tamil Nadu	2016	75.00
2.	Sree Bhavani Dyeing Cluster-Erode District-Setting of ZLD CETP with MD with Solar thermal	Tamil Nadu	2017	46.10
3.	Southern District Textile Processing Cluster-Kariyapatti village, Virudhunagar District, Setting up of ZLD CETP with CPP with Cogen	Tamil Nadu	2016	71.04

In order to protect the environment and the rivers of Siruvani and Noyyal, 18 ZLD based CETPs with 490 dyeing units were set up in and around Tirupur. Between 2010 and 2014, ₹ 187.50 crores and ₹ 112.50 crores were given by the Central and the State Governments respectively, as subsidy for setting up of Zero Liquid Discharge Systems in 18 Common Effluent Treatment Plants (CETPs), in Tirupur District, Tamil Nadu. Further, an Interest Free Loan of ₹ 203.29 crores was also provided by the State Government. Thereafter, Government of India, in 2016, sanctioned a further sum of ₹ 200.00 crores as Interest Free Loan to the eighteen CETPs at Tirupur through the State Government. In all, an assistance of ₹ 703.29 crores has been given as subsidy/loan by the Central and State Governments.

(c) and (d) No proposal has been received.

(e) and (f) Questions Do not arise.

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasikala Pushpa Ramaswamy is absent. Even if the Member is not there, we have a practice so far to answer the question. We will rethink about it afterwards, but at least you have to answer it today.

श्री अजय टम्टाः सर, उत्तर सभा पटल पर...

श्री सभापतिः आपको यह बताना है कि सभा पटल पर प्रश्न का उत्तर रख दिया। श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I would like to know this from the hon. Minister. What efforts have been made by the Government of India to improve the

[Shri V. Vijayasai Reddy]
performance of the Common Effluent Treatment Plants in textile industries and textile towns to address the issue of coastal pollution and reduce the impact of industrial effluents on soil and groundwater?

श्री अजय टम्टाः महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सीईटीपी प्लांट, जो कि आईपीडीएस योजना के अंतर्गत है, उसमें 6 प्लांट्स भारत सरकार के माध्यम से लगाए गए हैं और उसमें राज्य सरकार का भी सहयोग है। जो क्लस्टर है या उद्यमी हैं, उनका भी उसमें सहयोग है। देश-भर में विशेष रूप से 18 प्लांट्स विशेष स्कीम के अंतर्गत लगाए गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी, उसके अनुसार उन प्लांट्स को लगाया गया है। आपने पूछा कि क्या ऐसे प्लांट्स और कहीं लगाए जाएँगे, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। हम राज्य सरकार से भी यह निवेदन करते हैं कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारी जो भी प्रोसेसिंग या डाइंग यूनिट है, उसके कारण पर्यावरण प्रभावित न हो। इसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हम इसमें कुछ करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के माध्यम से और संबंधित यूनिट की तरफ से जब केन्द्र को प्रस्ताव आएगा, तब उसमें हम कुछ करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवईः सर, भिवंडी, मालेगांव और धुले, ये तीन-चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल का काम होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ कोई टेक्सटाइल पार्क बनाने की सरकार की कोई स्कीम है? अगर नहीं है, तो क्या आप बनाएँगे?

श्री अजय टम्टाः सर, माननीय सदस्य जी के द्वारा जिन क्लस्टर्स का ज़िक्र किया गया है, उनके सम्बन्ध में मैंने पहले भी बताया कि हमें राज्यों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। जहां तक उनमें प्रदूषण की बात है, तो संबंधित क्लस्टर या उद्यमी के लिए हमारी योजना है। उन योजनाओं में 50 प्रतिशत या अधिकतम 75 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के सहयोग से दिया जाता है। उसमें राज्य सरकार का 25 परसेंट और ऋण के माध्यम से, उद्यमी के माध्यम से या क्लस्टर के माध्यम से 25 परसेंट लगाया जाता है। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी स्कीम के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो 65 पार्क बनाए जा रहे हैं, उन पर भी हम इस योजना को लागू करते हैं। चूंकि आपने बहुत सारे क्लस्टर्स का ज़िक्र किया है, वे राज्य सरकार से संबंधित होंगे। आप कृपा करके अगर उन्हें योजना के माध्यम से जानकारी देंगे, तो अच्छा रहेगा।

श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ-साथ जितने भी इंडस्ट्रियल टाउंस हैं, जहाँ भिन्न-भिन्न किस्म की इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, वहाँ से गंदा पानी या । effluents नदियों में जाता है। सर, अभी एक महीने पहले यह ख़बर आई थी कि....

MR. CHAIRMAN: Put your supplementary question.

श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, मैं इसी पर सप्लिमेंटरी पूछ रहा हूँ। गंगा पानी में जब गंदा पानी गिरा था, तो बहुत सारी मछलियाँ मर गई थीं। सर, गवर्नमेंट ने अभी बताया है। कि Zero Liquid Discharge System, यह टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। मुझे गवर्नमेंट से यह जानकारी प्राप्त

करनी है कि जितने भी इंडस्ट्रियल टाउंस हैं, क्या उन सब जगह इसको as a policy adopt करने के लिए सरकार विचार कर रही है?

MR. CHAIRMAN: Right. यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री अजय टम्टाः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने कहा कि प्रदूषण के कारण काफी नुकसान होते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि CETP के माध्यम से तीन प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले ट्रीटमेंट में प्रोसेस के बाद जो पानी निकलता है, उसको नदी में भी छोड़ सकते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट के माध्यम से ज़मीन को सिंचित करने का काम भी किया जाता है। थर्ड ट्रीटमेंट वह है, जो आपने बताया है, यानि Zero Liquid Discharge System. उसके माध्यम से हम पानी को 95 परसेंट प्रोसेस कर लेते हैं और उसको उसी यूनिट के अंदर reuse कर लेते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र अपने आपमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें खास तौर से प्रोसेसिंग में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। माननीय सदस्य जी ने कहा है कि हम इसको पॉलिसी में लेकर आएँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह ऑलरेडी पॉलिसी में है। हमारा भी राज्यों के साथ इसके लिए निवेदन होता है, क्योंकि इसमें राज्यों की भी भागीदारी होती है और पर्यावरण मंत्रालय का भी योगदान रहता है। मैं माननीय सदस्य जी से निवेदन करूंगा कि आपके ध्यान में इससे सम्बन्धित जो-जो बातें हैं, उनको आप अपने राज्य सरकार के माध्यम से उन समूहों के ध्यान में लाएँ, क्योंकि केन्द्र और राज्य के सहयोग से इसको लागू करना है।

Task Force on reducing import dependence

*155. DR. BANDA PRAKASH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government has set up a high level Task Force to identify various items and policy interventions to reduce dependence on imports and to suggest ways to cut import of those items which can be manufactured or explored in the country; and

(b) if so, the details thereof along with India's imports during the last three years, item-wise?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SURESH PRABHU) (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes Sir, a Task Force of this nature has been set up on 5th July, 2018 to identify various items and policy interventions for reducing import dependence of the country. The terms of reference of the Task Force, *inter alia*, includes identification of products for import substitution, assessment of domestic manufacturing capacity and identification of constraints in expanding domestic production. The details of India's imports, over the last three years, are given in the Annexure.